>

Title: Need to give adequate compensation to farmers whose land is being acquired by the subsidiary of Coal India Limited for coal mining in Chandrapur Parliamentary Constituency, Maharashtra-laid.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, देश में कोयला आधारित विद्युत निर्माण परियोजनाओं को सरकार द्वारा प्राथमिकता देने से कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी सी आई एल द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र चन्द्रपुर-वनी-आर्णी के अंतर्गत पश्चिमांचल कोयला क्षेत्र (वेकोली) द्वारा कई नई कोयला खाने खोलने तथ पुरानी कोयला खानो के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर किसानों की भूमि अधिगृहित की जा रही है । सी आई एल तथा उसके अधीनस्थ वेकोली द्वारा कोयले का उत्खनन तथा विपणन किया जाता हे । इससे उन्हें करोड़ों रूपये का फायदा होता हे । लेकिन किसानों को भूमि अधिग्रहण का जो मूल्य चुकाया जा रहा है और जो मौद्रिक मुआवजा दिया जा रहा हे वह काफी कम हे । अधिग्रहण और विस्थापन की अवस्था में किसानों को बेरोजगार होना पड़ता हे । भविष्य में आजीविका सुनिश्चित कराने के लिए भूमि के ऐवज में दी जा रही धनराशि कम होने से किसान अब अधिग्रहण के खिलाफ हो रही हैं । उनकी मांग जायज है, भूमि का बाजार मूल्य से अधिकतम मूल्य देने की मांग को वेकोली द्वारा स्वीकार्य नहीं करने से किसानों में असंतोष पैदा हो रहा है, अब तो जनाकोश की स्थिति विद्रोह तक पहुंची है । मांग के समर्थन में आंदोलन चल रहे हैं । किसानों को कम से कम आठ लाख रूपये प्रति एकड़ भूमि का दाम, रोजगार और समुचित पुनर्वास उपलब्ध कराना उनका स्वाभाविक अधिकार है । हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी द्वारा इसी तर्ज पर भूमि का मुआवजा दिया है । लेकिन कोयला क्षेत्र में भारी मुनाफा होने के बाद भी वेकोली द्वारा मांग को नकारना इसे लंबित रखने से कोयला खानों के भूमि अधिग्रहण में अड़चने आ सकती हैं । अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि हमारे क्षेत्र के किसानों को कोयला खाने तथा अन्य उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकतम मूल्य, रोजगार और समुचित पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए इसमें हस्तक्षेप कर निर्देश जारी करें ।